[2014] 10 एस.सी.आर. 458

एडमंड एस लिंगदोह

बनाम

मेघालय राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 2056/2014)

सितम्बर 16, 2014

[टी.एस.ठाकुर और आर. भानुमति, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 420, 120बी; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947: धारा 5(2) - ए-1, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू) के मुख्य अभियंता - आरोप है कि ए-1 ने एनईएचयू के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर क्रय समिति बनाई - इन सभी ने मिलकर 1982 से 1985 की अवधि के दौरान ए-4 और ए-5 से अत्यधिक दरों पर सीमेंट की क्रय की - सीमेंट की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किए बिना अत्यधिक दरें स्वीकार कर ली गईं - ए-1 को आईपीसी की धारा 420, 1208 और 1947 अधिनियम की धारा 5(2) के तहत और ए-4 को आईपीसी की धारा 420 सपठित 120बी के तहत दोषी ठहराए जाने को चुनौती दी गई - अभिनिर्धारित किया: इस बात के पर्याप्त साक्ष्य थे कि ए-1 द्वारा बढ़ी हुई दर पर ए-4 के उद्धरण को मंजूरी देने के लिए क्रय समिति को गुमराह किया गया था - मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर, अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया कि क्रय समिति में गैर-तकनीकी सदस्य शामिल थे और तकनीकी सदस्य होने के नाते ए-1 ने क्रय समिति को बढ़ी हुई दर पर सीमेंट क्रय ने के लिए प्रेरित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी - •1 को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

सही दोषी ठहराया गया था - जहां तक ए-4 का संबंध है, डीलर होने के नाते, उसने खुद को गलत लाभ पहुंचाने और एनईएचयू को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए बढ़ी हुई कीमत उद्धृत की और इसलिए, उसे धारा 120-बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 के तहत दोषी ठहराया गया - हालांकि, ए-4 की उम्र और मामले के लंबित रहने की अवधि को देखते हुए, ए-4 की सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि में संशोधित कर दिया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 313 -- अभिनिर्धारित : जहां धारा 313 के तहत अभियुक्त अपनी जिरह में गोल-मोल जवाब देता है, तो उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। - लेकिन ऐसा अनुमान उन सबूतों का विकल्प नहीं हो सकता है जिन्हें अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पेश करना होगा।

विलम्ब/ अवधि का बीत जाना -- ऍफ़आईआर दर्ज करने में विलम्ब - अभिनिर्धारित: लगातार अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती।

ए 4 की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए और ए-1 की अपील को ख़ारिज करते हुए, न्यायालय ने -

अभिनिर्धारित किया : 1. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य और परिस्थितियां थीं कि क्रय समिति को ए-1 द्वारा 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई दर पर ए-4 के उद्धरण को मंजूरी देने के लिए गुमराह किया गया था। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ के दौरान जब ए-1 से सीमेंट की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसी का जिक्र करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक टालमटोल वाला जवाब था और इसे

परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए उसके खिलाफ सबूत के रूप में लिया गया था। जहां अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जिरह में गोल-मोल जवाब देता है, तो उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन इस तरह का अनुमान उन सबूतों का विकल्प नहीं हो सकता है जिन्हें अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पेश करना होगा। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, निचली न्यायालयों ने इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया कि क्रय समिति में गैर-तकनीकी सदस्य शामिल थे और तकनीकी सदस्य होने के नाते ए-1 ने क्रय समिति को सीमेंट क्रय ने के लिए प्रेरित करने में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बढ़ी हुई दर जब प्रासंगिक अवधि में बाजार दर रु.5/- से रु.10/- प्रति किलोग्राम थी। न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं थी। [पैरा 14, 19, 21 से 23] [467-डी; 470-सी-डी; 471-ई.पू.; 472-ए-सी]

बिष्णु प्रसाद सिन्हा और अन्य आसाम राज्य (2007) 11 एससीसी 467- भरोसा किया गया।

2. एफआईआर दर्ज करने में देरी: ए-1 ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके 12.12.1982 को 8 से 12 फर्मों से सीमेंट की आपूर्ति के लिए उद्धरण आमंत्रित की और डीपीसी की क्रय 1982 से 1985 के मध्य के दौरान की गई थी। कुलपति द्वारा 3.7.1985 को शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है क्योंकि सीमेंट की आपूर्ति 1982 से 1985 के मध्य तक लगातार की गई थी और यह एक जारी अपराध था। लगातार अपराध के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई समयावधि तय नहीं की जा सकती। [पैरा 28,30) [473-एफ-जी; 474-8-सी)

3. डीलर होने के नाते, ए-4 ने खुद को गलत लाभ पहुंचाने और एनईएचयू को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए बढ़ी हुई कीमत बताई। साजिश का सार यह है कि व्यक्तियों के बीच आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अधिनियम बनाने वाले एक या अन्य कार्यों को करने के लिए एक समझौता होना चाहिए। इस प्रकार साबित किए गए तथ्यों और आपत्तिजनक परिस्थितियों को पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे अभियुक्तों और उनके अपराध के बीच समझौते का सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सके। उच्च न्यायालय ने ए-4 को आईपीसी की धारा 420 सपठित धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया। ए-4 की उम्र सत्तर साल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उसका टाइप %II डायबिटीज का इलाज चल रहा है। यह मामला करीब तीन दशक से लटका हुआ है। मामले के लंबित रहने की अवधि और ए-4 की उम्र को ध्यान में रखते हुए और यह कि उसने पहले ही जुर्माना राशि का भुगतान कर दिया है और इस न्यायालय के आदेश के अनुसार राशि भी जमा कर दी है, ए-4 पर लगाए गए कारावास की सजा की अवधि आईपीसी की धारा 420 और आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोषसिद्धि को भुगती हुई अवधि में संशोधित किया जाएगा और विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने और इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार जमा की गई राशि के अलावा 2,50,000/- रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। [पैरा 32 से 35, 37, एच 38) [475-ई, जी; 476-ए, 8, डी, एच; 477-ए, एफ-जी]

न्याय निर्णयन सन्दर्भ :

(2007) 11 एससीसी 467 भरोसा किया गया पैरा 21

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2056/2014

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की शिलोंग पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2(एसएच)/2000 साथ में आपराधिक अपील संख्या 1(एसएच)/2000 और 1(एसएच)/1999 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.11.2010 से उत्पन्न।

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 2057-58/2014

हुज़ेफा अहमदी, वी.हरी पिल्लई, ठेमिस दिएन्ग्दोह, सुषा उन्नी, रोहन शर्मा, ऋषि मल्होत्रा, अरुणाभ चौधरी, वैभव तोमर, अनुपम लाल दास, अपीलार्थी की और से।

रंजन मुखर्जी, बी.वी.बलराम दास, पी.के.डे, पी.एल.निगम, अरविन्द कुमार शर्मा, प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

आर. भानुमति, न्यायाधिपति.

1. अनुमति अनुदत्त की गई।

2. एसएलपी (सीआरएल) संख्या 2203-2204/2011 से उत्पन्न ये अपीलें गौहाटी उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसमें धारा 420 आईपीसी, 1208 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता-प्रथम अभियुक्त (देव प्रसाद शर्मा) की सजा की पुष्टि की गई है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'पी.सी. अधिनियम') की धारा 5(2) और उस पर लगाई गई सज़ा में वृद्धि। चौथे अभियुक्त (एडमंड एस. लिंगदोह) ने एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 553/2011 को प्राथमिकता दी है, जिसमें अपने बरी होने के फैसले को पलटने और आईपीसी की धारा 1208 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को चुनौती दी गई है।

3. देव प्रसाद शर्मा (ए-1) की मृत्यु इस न्यायालय के समक्ष याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान 9.10.2011 को हुई थी और उनके कानूनी प्रतिनिधि को एसएलपी (आपराधिक) संख्या 2203-2204/11 से उत्पन्न आपराधिक अपील में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.201.1 द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया था और उनके बेटे देबाशीष शर्मा अपील की पैरवी कर रहे हैं।

4. संक्षेप में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि देवा प्रसाद शर्मा (प्रथम अभियुक्त) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के तत्कालीन मुख्य अभियंता (संक्षिप्त में 'एनईएचयू') थे, स्टेटनल रॉय (ए-2) लेखा अधिकारी थे, डब्ल्यू.एम.आर.वाहलांग (तीसरा अभियुक्त) तत्कालीन सहायक वित्त अधिकारी थे, एडमंड एस.लिंगदोह, मैसर्स ई.एस.एंटरप्राइज (ए-4) के मालिक और टी.एस.बरेह, मैसर्स प्रीमियर एंटरप्राइज (ए-5) के मालिक, एन.पी.गर्ग, कार्यकारी अभियंता, श्री जी.एल.शर्मा, जूनियर इंजीनियर, संजय, वरिष्ठ तकनीकी सहायक और एनईएचयू के निर्माण प्रभाग के अनुभाग अधिकारी, श्री एच.नॉनकिनारिह, ने वर्ष 1982 से 1985 के मध्य के दौरान कुछ काल्पनिक और गैर-मौजूद फर्मों से अत्यधिक दर पर डैम्प प्रूफ सीमेंट की क्रय के लिए मिलकर काम किया है। इस मिलीभगत को आगे बढ़ाते हुए, यह आरोप लगाया गया है कि ए-1 ने 12 फर्मों से 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से डैम्प प्रूफ सीमेंट (डी.पी.सी.) की आपूर्ति के लिए 12.12.1982 को उद्धरण आमंत्रित किया था। हालांकि उस समय वास्तविक बाजार मूल्य 5/- से 7/- रुपये प्रति किलोग्राम था। भले ही क्रय समिति ने सामग्री की आपूर्ति के लिए केवल दो फर्मों को मंजूरी दी थी। ए-1 पर आरोप है कि उसने उपलब्ध भण्डारण और वास्तविक आवश्यकता का पता लगाए बिना कई फर्मों और व्यक्तियों से ऑर्डर दिए, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में खरीदी गई सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। एनईएचयू के तत्कालीन कुलपति डॉ. बी.डी.शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और सीबीआई द्वारा अन्वेषण शुरू किया गया । अन्वेषण के दौरान, सीबीआई. ने ए-1 से ए-3, मैसर्स

ई.एस.एंटरप्राइजेज (ए-4) फर्म के मालिक श्री एडमंड एस. लिंगदोह, मैसर्स प्रीमियर एंटरप्राइजेज (ए-5) के श्री टी. एस. बरेह और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला पाया और उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 120बी के साथ आई.पी.सी. की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (डी) के साथ पठित धारा 5(2) के तहत आरोप पत्र दायर किया। अन्वेषण स्तर पर, अन्य लोगों को मामले से हटा दिया गया था और केवल ए-1 से ए-5 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने ए-1 से ए-3 के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 120बी, आई.पी.सी. की धारा 420 और पी.सी. अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (डी) के तहत आरोप तय किए, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। जहां तक ए-4 और ए-5 का संबंध है, उनके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 120बी और 420 के तहत आरोप तय किए गए थे। विचारण न्यायालय ने ए-1 को आई.पी.सी. की धारा 120बी के साथ आई.पी.सी. की धारा 420 और पी.सी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दोषी ठहराया और उसे कारावास की सजा सुनाई। ए-2 से ए-5 को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

5. ए-2 से ए-5 को दोषमुक्त किए जाने से व्यथित होने और पहले अभियुक्त के लिए सजा बढ़ाने की मांग करते हुए, सीबीआई ने विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि और कारावास की सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले अभियुक्त पर लगाए गए दंड को बढ़ा दिया और पहले अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। ए-1 की दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा उस पर लगाए गए दंड और उच्च न्यायालय द्वारा सजा में वृद्धि का विवरण इस प्रकार हैः

विचारण न्यायालय		उच्च न्यायालय	
दोषसिद्धि	सजा	दोषसिद्धि	सजा
धारा 120 बी आईपीसी	4 महीने साधारण कारावास और 15,000/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम में 2 महीने साधारण कारावास	धारा 120 बी आईपीसी	3 साल कठोर कारावास और 50,000/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम में 1 साल कठोर कारावास
धारा 420 आईपीसी	6 महीने साधारण कारावास और 15,000/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम में 2 महीने साधारण कारावास	धारा 420 आईपीसी	5 साल कठोर कारावास और 1,00,000/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम में 1 साल कठोर कारावास
धारा 5(2) पीसी अधिनियम	1 साल साधारण कारावास और 25,000/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम में 2 महीने साधारण कारावास	धारा 5(2) पीसी अधिनियम	5 साल कठोर कारावास और 1,00,000/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम में 1 साल कठोर कारावास

6. उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीनता के दौरान ए-2 की मृत्यु हो गई। 3 से 5 अभियुक्तों को दोषमुक्ति के फैसले को पलट दिया गया और उन्हें भा.दं.सं. सी. की धारा 120 बी और भा.दं.सं. सी. की धारा 420 के तहत दोषी ठहराया गया। जहाँ तक सजा की मात्रा लागू करने की बात है, उच्च न्यायालय ने धारा 235(2) सीआर.पी.सी. के तहत सजा की मात्रा के संबंध में अभियुक्त 3 से 5 को अवसर देने के बाद उचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामले को विचारण न्यायालय में भेज दिया। दोषमुक्ति के आदेश को वापस लेने के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी हमारे सामने हैं। इस न्यायालय के दिनांक 31.01.2011 के आदेश के अनुसार, विचारण न्यायालय ने चौथे अभियुक्त को सजा सुनाने का आदेश पारित किया। भा.दं.सं. सी. की धारा 420

और भा.दं.सं. सी. की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए चौथे अभियुक्त को क्रमशः पांच साल और तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया।

7. हमने अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को सुना है और हमने उस पर अपना उचित विचार किया है।

8. रीः आपराधिक अपील में पहला अभियुक्त देव प्रसाद शर्मा (मृत होने के बाद से): प्रथम अभियुक्त संबंधित समय में एनईएचयू का मुख्य अभियंता था और प्रथम अभियुक्त और ए-2 और ए-3 क्रय समिति में तकनीकी सदस्य थे। 12.12.1982 को, प्रथम अभियुक्त ने आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता का उल्लेख किए बिना डैम्प प्रूफ सीमेंट (डीपीसी) की आपूर्ति के लिए 12 फर्मों से सीलबंद उद्धरण आमंत्रित किए। जवाब में, छह फर्मों से उद्धरण प्राप्त हुए और 6.4.1983 को उसकी जांच की गई, जिसे मानदंडों और प्रक्रिया का उल्लंघन कहा गया और मैसर्स प्रीमियर एंटरप्राइजेज(ए-5) द्वारा 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर उद्धृत की गई। और मैसर्स एडमंड एस.लिंगदोह (ए-4) को सबसे कम पाया गया और तुलनात्मक विवरण देने के बाद, ए-1 ने तारीख के साथ अपना प्रारंभिक जोड़ा।

9. 7.04.1983 को, ए-1 ने 2 मीट्रिक टन (एमटी) की आपूर्ति के लिए टी.एस.बरेह (ए-5) से संबंधित ए-4-एम/एस एडमंड एस.लिंगदोह और एम/एस प्रीमियर एंटरप्राइज की चार अलग-अलग फर्मों को ऑर्डर दिया। प्रत्येक उद्धृत मूल्य 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम पर 04.06.1983 को दिए गए ऑर्डर और उद्धृत कीमतों के संदर्भ में, चौथे आरोपी ने अपनी फर्म मैसर्स एडमंड एस.लिंगदोह और मैसर्स ई.एस.एंटरप्राइज और मैसर्स टी.एस.बरेह के माध्यम से 42.75 रुपये प्रति की दर पर डीपीसी की आपूर्ति की। किलोग्राम 06.07.1983 को, एनईएचयू की क्रय समिति, जिसमें पहला आरोपी तकनीकी

सदस्य था, ने डीपीसी के कराया के लिए चौथे आरोपी और मेसर्स प्रीमियर एंटरप्राइजेज द्वारा उद्धृत 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर को मंजूरी दे दी।

10. पहले अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ए-1 ने दो फर्मों मैसर्स प्रीमियर एंटरप्राइजेज और मैसर्स एडमंड्स एस. लिंगदोह-चौथे अभियुक्त की दरों को 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मंजूरी देने के लिए क्रय समिति को प्रेरित किया था और चूंकि अनुबंध सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया गया था, इसलिए ए-1 द्वारा डीपीसी को अत्यधिक मूल्य पर क्रय के लिए धोखे से क्रय समिति को प्रेरित करने का कोई सवाल ही नहीं था और यह क्रय समिति ही थी जिसने अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए बोली लगाने वालों द्वारा उद्धृत कीमतों के तुलनात्मक विवरण के आधार पर दर को मंजूरी दी।

11. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि क्रय समिति द्वारा मामले को उठाए जाने से पहले भी पहले अभियुक्त द्वारा उद्धरण जारी किए गए थे और एनईएचयू के मुख्य अभियंता के रूप में पहले अभियुक्त को तत्कालीन प्रचलित बाजार दर और तकनीकी सदस्य के रूप में पता होना चाहिए था। क्रय समिति प्रथम अभियुक्त को तत्कालीन प्रचलित बाजार दर पर डीपीसी के क्रय में गैर-तकनीकी सदस्यों की सहायता करनी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पहले अभियुक्त के अपराध को लाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं कि उसने क्रय समिति को 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई दर पर डीपीसी क्रय करने के लिए प्रेरित किया।

12. पीडब्लू-6, श्री ओ.डी.शिरा, 1983 के दौरान प्रशासन के तत्कालीन सहायक पंजीयक, एनईएचयू क्रय समिति के संयोजक थे और उन्होंने 6.7.1983 को क्रय समिति की बैठक बुलाई। प्रदर्श पी1 6.7.1983 पर आयोजित क्रय समिति की बैठक से संबंधित फाइल है। प्रदर्श P1(1) के अनुसार, डीपीसी की क्रय के लिए कोई एजेंडा नहीं था।

हालाँकि, पहला अभियुक्त वस्तु को क्रय समिति के समक्ष पेश करने में कामयाब रहा, एजेंडा को संकल्प संख्या 14 में जगह मिली [प्रदर्श पी1(5)] उमशिंग में विभाग परिसर में उपयोग के लिए डैम्प सील वॉटर प्रूफिंग कंपाउंड के क्रय से संबंधित है। क्रय समिति ने अपीलार्थी/चौथे अभियुक्त और मैसर्स प्रीमियर एंटरप्राइजेज, जोवाई द्वारा उद्धृत 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की सबसे कम दर को स्वीकार किया। पीडब्लू-6 के साक्ष्य और पी1(5) के तहत संकल्प के आधार पर, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए इससे पहले कि क्रय समिति ने दर को मंजूरी दे दी, अभियुक्त नंबर 1 द्वारा पहले से ही उद्धरण आमंत्रित किए गए थे और ए1 क्रय समिति में तकनीकी सदस्यों में से एक होने के नाते चौथे अभियुक्त और मेसर्स प्रीमियर एंटरप्राइजेज द्वारा उद्धृत 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर को मंजूरी देने के लिए क्रय समिति की बैठक में आइटम पेश करने में कामयाब रहा। चूंकि ए-1 को क्रय समिति ने विश्वास में लिया था।

13. अपने साक्ष्य में पीडब्लू-9, श्रीमती एम.आर.मावलोंग, जो फरवरी 1980 से मार्च 1984 तक एनईएचयू के तत्कालीन पंजीयक थे, ने कहा कि मुख्य अभियंता होने के नाते पहला अभियुक्त क्रय समिति का तकनीकी सदस्य था और "क्रय समिति तकनीकी सदस्य के सुझाव पर निर्भर थी जो डीपीसी की दर के संबंध में मुख्य अभियंता के पद पर था।" क्रय समिति में तकनीकी सदस्यों को रखने का उद्देश्य तकनीकी प्रकृति के किसी भी मामले में गैर-तकनीकी सदस्यों की सहायता करना और संस्था के लिए उक्त वस्तु की उपयोगिता, प्रचलित दर और आवश्यक मात्रा के संबंध में उनका मार्गदर्शन करना था। क्रय समिति में तकनीकी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाती है और यह उम्मीद की जाती है कि तकनीकी सदस्य अर्थात् प्रथम अभियुक्त (देव प्रसाद शर्मा) और द्वितीय और तृतीय अभियुक्त अपने तकनीकी ज्ञान का योगदान दें और प्रचलित बाजार दर पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री की क्रय करने के लिए क्रय समिति को अपनी सर्वोत्तम संभव राय, सुझाव और सलाह दें। हम इस तर्क में

कोई सार नहीं पाते हैं कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि तकनीकी सदस्यों ने प्रथम अभियुक्त और ए-2 और ए-3 ने क्रय समिति को गुमराह किया है और क्रय समिति ने डीपीसी की क्रय करने का निर्णय अपने दम पर लिया था।

14. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को उचित ठहराने वाले पर्याप्त सबूत और परिस्थितियां हैं कि क्रय समिति को प्रथम अभियुक्त द्वारा चौथे अभियुक्त-मैसर्स एडमंड एस. लिंगदोह और मैसर्स प्रीमियर एंटरप्राइजेज के 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम के उद्धरण को मंजूरी देने के लिए गुमराह किया गया था। इसे मजबूत करने के लिए, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कुछ तथ्यों और परिस्थितियों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं:

(i) क्रय समिति द्वारा दर की मंजूरी से पहले, ए-1 द्वारा अपने दम पर आमंत्रित डीपीसी की आपूर्ति के लिए पांच उद्धरण पहले से ही अस्तित्व में थे;

(ii) प्रदर्श पी1 (1) के अनुसार, 6.7.1983 को आयोजित क्रय समिति की बैठक में डीपीसी की क्रय के लिए कोई एजेंडा नहीं था और उक्त एजेंडा डीपीसी की क्रय के संबंध में प्रस्ताव संख्या 14 में प्रदर्श पी1(5) के माध्यम से पेश किया गया था और ए-1 क्रय समिति में एक तकनीकी सदस्य होने के नाते डीपीसी की क्रय के लिए आइटम को एजेंडे में से एक के रूप में पेश करने में कामयाब रहा।

(iii) मुख्य अभियंता होने के नाते प्रथम अभियुक्त ने डीपीसी की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर का पता लगाने के लिए उद्धरण या किसी अन्य तरीके द्वारा सर्वेक्षण के लिए कदम नहीं उठाए;

(iv) क्रय समिति डीपीसी की दर के संबंध में तकनीकी सदस्यों-प्रथम अभियुक्त और अन्य लोगों के सुझाव पर निर्भर थी।

(v) प्रथम अभियुक्त ने डीपीसी के उपलब्ध भंडार या एनईएचयू के लिए डीपीसी की वास्तविक आवश्यकता का पता नहीं लगाया;

(vi) प्रथम अभियुक्त ने 12 फर्मों से उद्धरण आमंत्रित किए जिनमें से केवल दो फर्मों को क्रय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

15. ए-1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, यह निर्णायक रूप से नहीं माना जा सकता है कि डीपीसी की प्रासंगिक समय पर तत्कालीन प्रचलित बाजार दर रु.5/- से रु.6/- प्रति कि.ग्रा. थी क्योंकि उस प्रभाव का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या उस समय खुले बाजार में डीपीसी की कोई मूल्य सूची अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी और जबकि न्यायालयों ने मौखिक गवाही के आधार पर ए-1 को दोषी ठहराने में घोर गलती की है। यह आगे तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने पहले अभियुक्त के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ी को पूरा करने के लिए सबूत के एक टुकड़े के रूप में धारा 313 सीआर.पी.सी. के तहत दर्ज ए-1 के उत्तरों पर भरोसा करने में गलती की।

16. यह साबित करने के लिए कि शिलांग में डीपीसी की तत्कालीन बाजार कीमत 5/- रुपये से लेकर 10/- रुपये प्रति किलोग्राम तक थी, अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। पीडब्लू-5, श्री सतिंदर बावा, जो बावा पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म के निदेशक हैं, जो वर्ष 1965 से पेंट और वाटर प्रूफ कंपाउंड का निर्माण करती है और उनकी फर्मों के उत्पादों को मैसर्स प्रीमियर एंटरप्राइजेज और अन्य सहित विभिन्न वितरकों को बेचा जाता है और मेघालय और जोवाई क्षेत्र सहित पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में और उत्पादों को 1982-1983 के दौरान भी बेचा गया था। अपने साक्ष्य में पीडब्लू-5 ने कहा कि 1982-1984 के दौरान, दिल्ली में 50 किलोग्राम डैम्प प्रूफ सीमेंट 80/- रुपये से 85/- रुपये के बीच बेचा गया था, जिसमें कर भी शामिल थे और एक किलोग्राम पैकेट, दिल्ली में रु.2.80/- से रु.3.80/- पर बेचा जाता था। पीडब्लू 5 ने आगे कहा

कि शिलांग में एक किलोग्राम डीपीसी की दर तब रु.6/- से रु.7/- प्रति किलोग्राम, जिसमें कर, परिवहन और लाभ शामिल हैं।

17. पीडब्लू-16, श्री संतोष कुमार चचन, शिलांग में बरबज़र के मैसर्स गजानंद चचन के मालिक हैं जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट सहित हार्डवेयर, पेंट और निर्माण सामग्री से संबंधित है। पीडब्लू-5 के साक्ष्य के अनुसार, पीडब्लू-16 मैसर्स गजानंद चचन भी उन फर्मों में से एक है जिन्हें पीडब्लू-5 द्वारा डीपीसी और पेंट की आपूर्ति की गई थी। पीडब्लू-5 के साक्ष्य की पुष्टि करते हुए, पीडब्लू-16 ने कहा कि उनकी फर्म 1982-1984 के दौरान वाटर प्रूफिंग सीमेंट का काम कर रही थी और वह 1983-1984 के दौरान दिल्ली, कलकत्ता और कभी-कभी गुवाहाटी से पेंट और वाटर प्रूफिंग सीमेंट क्रय ते थे, और उस अवधि के दौरान वाटर प्रूफिंग सीमेंट की कीमतें रु.5/- प्रति किलोग्राम थी जो शिलांग में बेचा गया था। पीडब्लू 5 और 16 के साक्ष्य से यह पूरी तरह से स्थापित होता है कि संबंधित समय में दिल्ली डीपीसी की बाजार दर रु.2.80 से रु.3.80 प्रति किलोग्राम थी और यह शिलोंग में यह दर रु.6/- से रु.7/- प्रति किलोग्राम थी और 42.75 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर बढ़ी हुई थी और चौथे अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत और पहले अभियुक्त द्वारा स्वीकार किए गए उद्धरण गलत उद्देश्य से थे।

18. पीडब्लू 5 और 16 की जांच करके तत्कालीन प्रचलित बाजार दर स्थापित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-13, श्री एन.पी.गर्ग की भी जांच की है, जिन्होंने 1984 से एनईएचयू में कार्यकारी अभियंता के रूप में काम किया है, जो निर्माण कार्य में डैम्प सील सीमेंट के उपयोग के बारे में भी जानते हैं। पीडब्ल्यू-13, प्रदर्श पी5 के माध्यम से दिनांक 6.9.1983 की अवधि के लिए वाहजरैन में इंटेक वॉटर टैंक के निर्माण कार्य के लिए कार्य फ़ाइल और आइटम 7(17) द्वारा वाटर प्रूफिंग कंपाउंड के लिए 10/- रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान किया गया था। (डीपीसी) सहित अन्य मद से कार्य ठेकेदार हंसराज जैन द्वारा कराया गया तथा राशि का भुगतान

भी उन्हें कर दिया गया। पीडब्लू-13 और प्रदर्श पी5 के साक्ष्य का उल्लेख करते हुए, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज किया कि बचाव पक्ष ने न तो उनकी विश्वसनीयता पर महाभियोग चलाया और न ही प्रदर्श पी5 विधेयक को चुनौती दी, जिसके अनुसार रुपये 10/- प्रति किलोग्राम का भुगतान जल प्रूफिंग यौगिक के लिए डीपीसी के लिए किया गया था और यह कि प्रदर्श पी5 अब तक पुष्टि करने वाला सबूत होगा क्योंकि जल प्रूफिंग परिसर (डीपीसी) की दर 1983 की अवधि के दौरान रु.10/- प्रति किलोग्राम थी। पी.डब्ल्यू.-5 और पी.डब्ल्यू.-16, डीपीसी में विक्रेताओं के साक्ष्य और पी.डब्ल्यू.-13 द्वारा कही गई पूर्व कार्य फाइल (प्रदर्श पी5) से अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि डीपीसी की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर रु.5/- से रु.10/- प्रति किलोग्राम थी।

19. 6.07.1983 को आयोजित क्रय समिति की बैठक में डीपीसी की क्रय के लिए विषय रखने से पहले, जैसा कि विचारण न्यायालय ने बताया था, डीपीसी की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था और न ही प्रथम अभियुक्त द्वारा कोई अन्य तरीका अपनाया गया था। धारा 313 सीआर.पी.सी. के तहत पूछताछ के दौरान, जब पहले अभियुक्त से डीपीसी की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर के बारे में पूछा गया, तो पहले अभियुक्त ने कहा कि वह इसके बारे में नहीं जानता था। उसी का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक टालमटोल जवाब है और इसे परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ सबूत के रूप में लिया गया था।

20. जहां तक धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए पहले अभियुक्त के बयान को साक्ष्य के रूप में लेने का विवाद है, तो यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान को अभियुक्त के खिलाफ दोषी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। निस्संदेह, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जिरह

में पहले अभियुक्त के दिए गए बयानों का विस्तार से उल्लेख किया और इस प्रकार टिप्पणी की: -

> "ए-1 ने इस बात पर हमला करने के लिए एक भी शब्द नहीं बोला कि संबंधित समय में शिलांग में डीपीसी का बाजार मूल्य 5/- रुपये से लेकर 10/- रुपये तक था। उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें उस समय डीपीसी की बाजार दर के बारे में जानकारी नहीं थी या डीपीसी की स्वीकृत दर 42.75 रुपये थी। ये टालमटोल वाले उत्तर, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-13 के साक्ष्य और एक्सटेंशन पी-5 के आइटम नंबर 7(17) के साथ मिलकर, ए-1 के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला में लिंक को पूरा करते हैं।"

इस तरह की टिप्पणी के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि वे टालमटोल वाले उत्तर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दिए बयानों के साथ मिलकर A-1 के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी को पूरा करें।

21. जहां अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जिरह में टालमटोल जवाब देता है, उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा निष्कर्ष उस साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकता है जिसे अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को लाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान कोई सबूत नहीं है। बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम अन्य बनाम असम राज्य (2007) 11 एससीसी 467 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज उसके बयान पर आधारित नहीं हो सकती है, जिसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह केवल स्पष्टीकरण के माध्यम से अभियुक्त का रुख या संस्करण है जो उसके खिलाफ उपस्थित होने वाले अपराध साक्ष्य/परिस्थितियों को समझाता है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत

अभियुक्त द्वारा बचाव में दिए गए बयान को निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में अन्य सबूतों को विश्वास दिलाने के लिए सहायता ली जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दिए गए बयानों को अलग से नहीं बल्कि अन्य अभियोजन साक्ष्य के संयोजन में माना जाना चाहिए।

22. वर्तमान मामले में, ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पहले अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंचा और दोषसिद्धि को आधार बनाया। जैसा कि ऊपर दिए गए उच्च न्यायालय के तर्कों से देखा जा सकता है, धारा 313 सीआरपीसी के तहत पहले अभियुक्त का बयान A-1 के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक कड़ी के रूप में PW-6 और PW-13 के साक्ष्य और Ext.P5 के आइटम 7(17) के साथ लिया गया था। जैसा कि पहले विस्तार से बताया गया है, पहले अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को अलग से नहीं बल्कि अन्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के संयोजन में माना गया था। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं मिला कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने की एक कड़ी के रूप में पहले अभियुक्त का बयान लेने में गलती की।

23. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए कि गैर-तकनीकी सदस्यों वाली क्रय समिति, जिसमें पहला अभियुक्त एक तकनीकी सदस्य था, ने क्रय समिति को 42.75 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई दर पर डीपीसी क्रय करने के लिए प्रेरित करने में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब संबंधित अवधि में तत्कालीन प्रचलित बाजार दर रु.5/- से रु.10/- प्रति किलोग्राम थी और हम न्यायालयों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं देखते हैं।

24. मंजूरी की वैधता के बारे में तर्कः प्रदर्श पी19 ए-1 के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी आदेश है और यह मेघालय सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के तहत था। पीडब्लू-18, श्री खारकोंगोर, राजनीतिक विभाग में सचिव, मेघालय सरकार की जांच की गई, जिनके द्वारा प्रदर्श पी9 मंजूरी आदेश प्रदर्शित किया गया था।

25. ए-1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीसी अधिनियम की धारा 6 के तहत "कोई भी न्यायालय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है।" और जहां तक ए-1 का संबंध है, मुख्य सचिव ए-1 को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है और ए-1 को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया था और मेघालय के राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकरण हैं, और इसलिए मंजूरी राज्यपाल के संतोष के लिए होनी चाहिए और मुख्य सचिव केवल मंजूरी का संचार करने वाला अधिकारी है और अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है कि नियुक्ति प्राधिकरण-मेघालय के राज्यपाल संतुष्ट थे कि ए-1 पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी को मंजूरी देने के लिए प्रासंगिक सामग्री उनके सामने रखी गई थी।

26. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमें पीडब्लू-18 के साक्ष्यों से अवगत कराया और प्रस्तुत किया कि मुख्य सचिव ने उनके समक्ष रखी गई सीबीआई की रिपोर्ट और फ़ाइल की नोट शीट में दर्शाई गई अन्य सामग्रियों के आधार पर मंजूरी दी थी। और फिर ए-1 पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई और ए-1 पर मुकदमा चलाने के लिए वैध मंजूरी है। पीडब्लू-18 के साक्ष्यों का हवाला देते हुए, अदालतों ने पाया कि तत्कालीन मुख्य सचिव ने सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी थी, जैसा कि पुलिस की नोट शीट में दर्शाया गया है और मंजूरी आदेश में कोई खामी नहीं है।

27. भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 (2) के अनुसार, राज्यपाल के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए सभी आदेशों और अन्य लिखतों को राज्यपाल द्वारा

बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जाएगा और इस तरह से प्रमाणित आदेश या लिखत की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि यह राज्यपाल द्वारा बनाया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। पीडब्लू-18 को यह सुझाव नहीं दिया गया था कि मुख्य सचिव के पास राज्यपाल के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और उपकरणों को प्रमाणित करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण के दौरान, पहले अभियुक्त ने भी फाइल पेश करने पर जोर नहीं दिया और न ही यह सुझाव दिया कि मंजूरी आदेश को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 का उल्लेख करते हुए, विचारण न्यायालय ने कहा कि राज्य के पास कुछ नियम होने चाहिए जहां राज्यपाल के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों को राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, विचारण न्यायालय ने मंजूरी की वैधता को चुनौती देने वाले पहले अभियुक्त के तर्क को नकार दिया। हम प्रथम अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की मंजूरी की वैधता को चुनौती देने वाले विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

28. एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में तर्कः अभियुक्त ए-1 ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके डैम्प प्रूफ सीमेंट (डीपीसी) की आपूर्ति के लिए 12 फर्मों से 12.12.1982 को उद्धरण आमंत्रित किया और डीपीसी की क्रय 1982 से 1985 के मध्य के दौरान की गई थी। प्रदर्श पी11 शिकायत डॉ.बी.डी.शर्मा, कुलपति, एनईएचयू, शिलांग, मेघालय द्वारा 3.7.1985 को दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता/प्रथम अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि एफआईआर लगभग दो साल बाद दर्ज की गई थी जो इसकी वास्तविकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। इससे भी अधिक, जब जिस कुलपति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उससे गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई।

29. इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि डीपीसी 1982 से 1985 के मध्य के दौरान प्राप्त किया गया था और अपराध एक निरंतर अपराध होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी और शिकायतकर्ता-कुलपति की गैर-जांच अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं थी।

30. केवल एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। जैसा कि प्रत्यर्थी-सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया, डीपीसी की आपूर्ति 1982 से 1985 के मध्य तक लगातार की गई थी और यह एक निरंतर अपराध था। अपराध जारी रहने के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रथम अभियुक्त ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके क्रय समिति को रुपये 42.75 प्रति किलोग्राम की अत्यधिक दर पर डीपीसी की क्रय के लिए प्रेरित किया और केवल जब साजिश सामने आई, तो कुलपति ने शिकायत दर्ज कराई। शक्तियों का दुरुपयोग और आर्थिक लाभ प्राप्त करने और गलत नुकसान करने के मामलों में, शिकायत दर्ज करने और प्राथमिकी दर्ज करने के समय को हत्या, डकैती और हमले आदि के अन्य मामलों की तरह तुरंत शिकायत दर्ज करने की कसौटी पर नहीं माना जा सकता है, जहां अतिशयोक्ति और अलंकरण की संभावनाएं हैं। आधिकारिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा पद के दुरुपयोग और गलत नुकसान के मामलों में, अभियोजन पक्ष का मामला दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य आधिकारिक गवाहों के मौखिक साक्ष्य पर आधारित होता है और शायद ही मनगढ़ंत और मनमाने संस्करण की शुरुआत की कोई संभावना होती है। हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अभियोजन मामले की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करती है।

31. धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध का सार यह है कि एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने वाला एक लोक अधिकारी अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। "दुर्व्यवहार" शब्द का अर्थ है, दुरुपयोग अर्थात अपने पद का उपयोग किसी ऐसी चीज़ के लिए करना जिसके लिए इसका इरादा नहीं है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया कि पहले अभियुक्त, मुख्य अभियंता क्रय समिति के तकनीकी सदस्य होने के नाते, यह उनका कर्तव्य था कि वे डीपीसी की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर के बारे में क्रय समिति को सलाह दें ताकि एनईएचयू बाजार दर पर डीपीसी क्रय कर सके। पहला अभियुक्त मुख्य रूप से अपराध करने के लिए जिम्मेदार था और पहले अभियुक्त ने मुख्य अभियंता और तकनीकी सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके डीपीसी की बढ़ी हुई दर रु.42.75 प्रति किलोग्राम तब स्वीकृत किया गया जब यह स्थानीय बाजार में 5/- रुपये से 10/- रुपये प्रति किलोग्राम तक की कीमत पर उपलब्ध था और A-1 ने अपने लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया और 4 और 5 पर भी आरोप लगाया और एनईएचयु को रुपये 49 लाख का गलत नुकसान पहुंचाया। पहले अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 120 बी और भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत और पी.सी. अधिनियम की धारा 5 (2) (डी) के तहत भी दोषी ठहराया गया था। अपराध की गंभीरता और एनईएचयू को हुए नुकसान की सीमा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने विभिन्न अपराधों के लिए लगाए गए कारावास की सजा को सही ढंग से बढ़ाया, जिसके लिए पहले अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था और हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। पहले अभियुक्त द्वारा दायर और अब उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा की गई अपील विफल हो जाती है और उसे खारिज किया जाता है।

32. रीः चौथे अभियुक्त एडमंड एस.लिंगदोह के खिलाफ दाण्डिक अपील: चौथे अभियुक्त एडमंड एस.लिंगदोह, मैसर्स एडमंड एस.लिंगदोह के मालिक ने भी एनईएचयू को डीपीसी

की आपूर्ति रुपये 42.75 प्रति किलोग्राम की दर से की थी। डीपीसी के साथ काम करने वाले व्यापारी होने के नाते, एडमंड को डीपीसी की बाजार दर का पता होना चाहिए; डीपीसी की तत्कालीन बाजार दर उन दिनों में 5/- रुपये से लेकर 10/- रुपये तक थी। भले ही ए-1 उक्त बाजार मूल्य पर चुप था, चौथे अभियुक्त, एडमंड ने डीपीसी के बाजार मूल्य का खुलासा किया होगा और डीपीसी के तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य का हवाला दिया होगा जो 5/- रुपये से 10 रुपये तक था, लेकिन चौथे अभियुक्त ने रुपये 42.75 प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई कीमत का हवाला दिया ताकि वह खुद को गलत तरीके से लाभ पहुँचा सके और एनईएचयू को गलत तरीके से नुकसान पहुँचा सके।

33. आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए; (i) कि अभियुक्त एक ऐसा कार्य करने के लिए सहमत हुआ या करने के लिए मजबूर किया गया जो अवैध था या अवैध माध्यमों से किया जाना था; (ii) कि समझौते के अनुसरण में अभियुक्तों में से एक द्वारा कुछ स्पष्ट कार्य किया गया था। षड्यंत्र का सार यह है कि भा.दं.सं. की धारा 120बी के तहत अधिनियम का गठन करने वाले एक या अन्य कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए। पहले अभियुक्त पर आरोप है कि उसने चौथे अभियुक्त और अन्य लोगों के साथ मिलकर एनईएचयू को रुपये 42.75 प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई कीमत पर डीपीसी की आपूर्ति करने की साजिश रची थी, जबकि उस समय की प्रचलित बाजार दर 5/- से 10/- रूपए प्रति किलोग्राम थी। साजिश को आगे बढ़ाते हुए, चौथे अभियुक्त ने छह मीट्रिक टन डीपीसी की आपूर्ति की और कहा कि इससे एनईएचयू को लगभग 6 लाख रुपये का गलत नुकसान हुआ।

34. षड्यंत्रकारियों के बीच समझौते का अनुमान आवश्यक निहितार्थ से लगाया जा सकता है और सिद्ध तथ्यों पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस प्रकार साबित तथ्यों और दोषपूर्ण परिस्थितियों को पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे अभियुक्त और

उनके अपराध के बीच समझौते का सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सके। चौथे अभियुक्त ने एनईएचयू को रुपये 42.75 प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई दर पर डीपीसी की आपूर्ति की और उसने अपने लिए और पहले अभियुक्त के लिए भी आर्थिक लाभ प्राप्त किया था और इस तरह एनईएचयू को गलत नुकसान पहुंचाया था। साक्ष्य और सिद्ध तथ्यों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति जाने के फैसले को सही ढंग से उलट दिया और चौथे अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया।

35. जहां तक चौथे अभियुक्त का संबंध है, उसे भी भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। धोखाधड़ी का अपराध दो घटकों से बना हैः "किसी भी व्यक्ति को धोखा देना और धोखाधड़ी या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना या इस बात पर सहमति देना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा।" पहले अभियुक्त के साथ मिलीभगत में, चौथे अभियुक्त ने रुपये 42.75 प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई दर पर डीपीसी का हवाला दिया और आपूर्ति की। चौथे अभियुक्त ने बेईमानी से एनईएचयू को डीपीसी क्रय करने के लिए प्रेरित किया। चौथे अभियुक्त ने यह रुख अपनाया है कि उसे शिलांग में डीपीसी की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर की जानकारी नहीं थी। एक सप्लायर के रूप में और डीपीसी से निपटने के रूप में, यह समझ से परे है कि चौथे अभियुक्त को प्रचलित बाजार दर की जानकारी नहीं थी। उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष के बयान को सही ही नकार दिया और चौथे अभियुक्त को धारा 420 सपठित धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया।

36. उच्च न्यायालय ने सजा के सवाल पर अभियुक्त को सुनने और उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को विचारण न्यायालय को भेज दिया। इस बीच, चौथे अभियुक्त ने इस न्यायालय में अपील की और विचारण न्यायालय को सजा न देने का निर्देश देने के लिए एक आवेदन भी दायर किया। दिनांक 31.01.2011 के आदेश

द्वारा इस न्यायालय ने आदेश दिया कि विचारण न्यायालय सजा के बिंदु पर आगे कार्यवाही करेगी और उचित आदेश पारित करेगी।

37. आदेश दिनांक 14.06.2011 द्वारा, विचारण न्यालय ने चौथे अभियुक्त को धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए व्यतिक्रम के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई; आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध के लिए, चौथे अभियुक्त को व्यतिक्रम के साथ 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया। चौथे अभियुक्त ने 14.06.2011 से 16.02.2012 तक कुल 248 दिन कारावास की सजा भुगती थी। इस न्यायालय के दिनांक 16.02.2012 के आदेश द्वारा, चौथे अभियुक्त पर लगाई गई सज़ा को निलंबित करने का आदेश दिया गया था, बशर्ते कि याचिकाकर्ता/चौथे अभियुक्त को रु.3,50,000/- की राशि जमा करनी होगी, जो कथित रूप से उसके द्वारा आपूर्ति की गई डीपीसी की कीमत के प्रति अर्जित अतिरिक्त राशि का लगभग 50% है। चौथे अभियुक्त की उम्र सत्तर साल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उसका टाइप II डायबिटीज का इलाज चल रहा है। यह मामला करीब तीन दशक से लटका हुआ है।

38. मामले के लंबित रहने की अवधि और चौथे अभियुक्त की उम्र को ध्यान में रखते हुए और उसने पहले ही जुर्माना राशि का भुगतान कर दिया है और इस न्यायालय के आदेश के अनुसार राशि भी जमा कर दी है। हमारे विचार में, आईपीसी की धारा 420 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दोषसिद्धि के लिए अपीलकर्ता-चौथे अभियुक्त पर लगाए गए कारावास की सजा की अवधि को पहले से ही पारित अवधि में संशोधित किया जाएगा और 2,50,000/- रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। विचारण न्यालय द्वारा लगाए गए जुर्माने के अलावा और इस न्यायालय के

आदेशों के अनुसार जमा की गई राशि। उक्त जुर्माने की राशि 2,50,000/- का भुगतान न करने पर चौथे अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा।

39. प्रथम अभियुक्त द्वारा अब उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया जाता है। चौथे अभियुक्त (एडमंड एस.लिंगदोह) द्वारा दायर अपील को ऊपर बताए गए हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

देविका गुर्जर

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****